भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 501
बुधवार, 22 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

कांगड़ा -चंबा धर्मशाला क्षेत्र में भूकंप का खतरा

†501. श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या **पृथ्वी विज्ञान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा-चंबा क्षेत्र में हाल ही में हुई भूकंपीय गतिविधियों पर ध्यान दिया है, जहाँ जून माह में 2.1 से 5.0 की तीव्रता वाले भूकंप के झटके दर्ज किए गए थे और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (एनजीआरआई) ने कांगड़ा-चंबा धर्मशाला क्षेत्र को भविष्य में 7.0 से अधिक तीव्रता वाले बड़े भूकंप की उच्च संभावना वाले क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र में भूकंप संबंधी निगरानी, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और आपदा संबंधी तैयारियों को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने राज्यों को भूकंप-रोधी भवन निर्माण मानकों को सख्ती से लागू करने के संबंध में हाल ही में कोई नए परामर्श या दिशानिर्देश जारी किए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) किसी बड़े भूकंप की स्थिति में जान-माल के नुकसान को कम करने के लिए तैयार की गई कार्ययोजना, संवेदनशील भवनों के सुदृढ़ीकरण की स्थिति और जन जागरूकता अभियानों का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का कांगड़ा-चंबा धर्मशाला क्षेत्र की नया भूकंपीय सूक्ष्म-क्षेत्रीकरण संबंधी अध्ययन करने तथा आपदा सुदृढ़ता के लिए राज्य को अतिरिक्त वित्तीय व तकनीकी सहायता प्रदान करने का विचार हैं?

उत्तर
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) जी हाँ। सरकार ने कांगड़ा-चंबा इलाके में भूकंप की गतिविधियों पर ध्यान दिया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय भूकंप केंद्र (NCS), राष्ट्रीय भूकंप नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश में भूकंपों की लगातार निगरानी करता है। जून 2026 के दौरान, राष्ट्रीय भूकंप केंद्र ने अपने 24×7 भूकंप निगरानी केंद्र के ज़रिए हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा-चंबा इलाके में कुल 16 भूकंपों का पता लगाया और उनकी रिपोर्ट दी, जबकि प्रश्न में 18 भूकंपों का ज़िक्र किया गया था। इन भूकंपों की तीव्रता के आधार पर जानकारी इस प्रकार है:

तीव्रता की रेंज	2.0 - 2.9	3.0 - 3.9	4.0 - 4.9	5.0 - 5.9
भूकंपों की संख्या	12	3	शून्य	1

(ख) कांगड़ा-चंबा-धर्मशाला क्षेत्र भूकंप के लिहाज़ से भारत के सबसे ज़्यादा जोखिम वाले जोन, यानी 'सिस्मिक ज़ोन V' में आता है। राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (एनजीआरआई) और दूसरे संस्थानों के वैज्ञानिक अध्ययन से पता चलता है कि टेक्टोनिक गतिविधियों की वजह से इस इलाके में 7.0 से ज़्यादा तीव्रता वाले बड़े भूकंप आ सकते हैं।

(ग) सरकार ने ' राष्ट्रीय भूकंपीय नेटवर्क' का विस्तार करके राष्ट्रीय भूकंप केंद्र द्वारा चौबीसों घंटे निगरानी सुनिश्चित करके भूकंप की निगरानी को मज़बूत किया है। अभी, राष्ट्रीय भूकंप केंद्र देश भर में 172 भूकंप मापी केंद्रों (सिस्मिक स्टेशनों) का राष्ट्रीय भूकंपीय नेटवर्क' संचालित करता है, ताकि 24×7 रियल-टाइम भूकंप की निगरानी की जा सके। इन 172 केंद्रों में से 7 केंद्र (शिमला, धर्मशाला, तिस्सा, सुंदरनगर, कल्पा, भाखड़ा और पोंग डैम) हिमाचल प्रदेश में हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण' (NDMA) राज्य सरकारों के साथ मिलकर मॉक ड्रिल, अधिकारियों और फर्स्ट रिस्पॉन्डर (आपातकालीन स्थिति में सबसे पहले पहुँचने वाले) की ट्रेनिंग, आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र को मज़बूत करने के ज़रिए भूकंप से निपटने की तैयारी को बढ़ावा देती है।

(घ) जी हाँ। सरकार ने नेशनल बिल्डिंग कोड (NBC), ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) के भूकंप-रोधी डिज़ाइन कोड और मॉडल बिल्डिंग बाय-लॉज़ के ज़रिए भूकंप-रोधी निर्माण को अपनाने और लागू करने के लिए परामर्श और गाइडलाइंस जारी की हैं। इन कोड को लागू करने की ज़िम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों की है।

(ङ) सरकार जोखिम का आकलन, तैयारी, क्षमता निर्माण, अहम बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और संबंधित अधिकारियों द्वारा जोखिम वाली महत्वपूर्ण इमारतों को रेट्रोफिटिंग (मजबूत बनाने) को बढ़ावा देने के ज़रिए जान-माल के नुकसान को कम करने की रणनीति अपनाती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भूकंप से सुरक्षा और तैयारी को बढ़ावा देने के लिए नियमित रूप से जन-जागरूकता अभियान, स्कूल और समुदाय में जागरूकता कार्यक्रम, मॉक ड्रिल और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है।

(च) वैज्ञानिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों द्वारा भूकंपीय माइक्रोज़ोनेशन अध्ययन किए जाते हैं। सरकार, आपदा से निपटने की क्षमता और तैयारी को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न आपदा प्रबंधन और रोकथाम योजनाओं के तहत हिमाचल प्रदेश सहित सभी राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता देती रहती है।

****